

विकास के लिए सबका साथ : शिवराज

हर क्षेत्र में पीपीपी माडल का प्रयोग करेंगे

मृगेन्द्र सिंह, भोपाल

खुद को सपनों का सौदागर मानने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ दिनों बाद ही पांच साल पूरे करने जा रहे हैं। वे प्रदेश में सत्तासीन रही गैर कांग्रेसी सरकारों के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं, जो पांच साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। कहना न होगा कि



शिवराज ने प्रदेश के विकास को सच्चे मन से नई दिशा देने की कोशिश की है। उनकी कुछ योजनाओं को पूरे देश में तारीफ मिली है, तो प्रदेश में विकास की दर में भी अल्लेखनीय इजाफा हुआ है। मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर भी उन्होंने विकास के जो नए सूत्र दिए हैं, उनसे साफ है कि मुख्यमंत्री आमजन को प्रदेश के विकास से

जोड़ना चाहते हैं। उनकी सोच है कि प्रदेश का चहुँमुखी विकास तभी हो सकता है, जब शासन के साथ आमजन भी इसमें सहभागी बने।

उनका कहना है कि जनता के मन में यह भावना पैदा करने में हम सफल रहे हैं कि मध्यप्रदेश हमारा है और सब मिलकर इसे नंबर वन राज्य बनाएंगे। जागरण से खास बातचीत में उन्होंने कहा

कि हम विकास के लिए जनता को संकल्पबद्ध करने में सफल रहे हैं। विकास के छह सूत्रों में निवेश के साथ रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को भी जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का तेजी से सर्वांगीण विकास हमारा लक्ष्य है, इसके लिए चौदह हजार करोड़ रुपए से अधिक के कार्य पीपीपी मोड में स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसानों के खेत तक जल्द से जल्द पानी कैसे पहुँचे, इसके लिए मंत्रियों का समूह बनाया गया है। खेती के साथ हार्टीकल्चर और पशुपालन को भी जोड़ा जा रहा है, ताकि गाँवों में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। श्री चौहान ने कहा कि सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए लघु सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा और ऐसी योजनाओं को हाथ में लिया जाएगा, जो एक साल में पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि कम पानी में अच्छी फसलों के लिए स्प्रिंकलर पद्धति का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए किसानों को सरकार और छूट देगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए कर्मा कल्चर के कारण शिक्षा का बंटोधार हो रहा था, जिसे अब सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में भी निजी

आठ मुख्यमंत्रियों ने की नए कानून की सराहना

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में लागू किये गये लोक सेवा प्रदाय गारंटी कानून की कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सराहना की है। उन्होंने बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, जम्मू कश्मीर के फारूख अब्दुल्ला, बिहार के नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ के रमन सिंह समेत गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने भी इसकी तारीफ की है।

स्कूलों के समान सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयास शुरू हो गए हैं। इसके साथ इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं, बड़े स्कूल चलाने वाले गरीब बच्चों को भी सरस्ती शिक्षा उपलब्ध कराएं। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए भी निजी क्षेत्रों की मदद ली जाएगी।